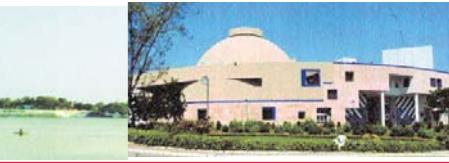


मंगलवार 29 अक्टूबर 2024, सीहोर



मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्णय से धर्मनगरी उज्जैन का वातावरण धर्ममय होगा



-मुख्यमंत्री का अखाड़ा परिषद उज्जैन के संत-जनों ने किया सम्मान

भोपाल (ए)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के धर्मनगरी उज्जैन में साथ संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडले शर इत्यादि को स्थाई आश्रम बनाने की अनुमति दिए जाने के निर्णय से उज्जैन नारी का वातावरण धर्ममय होगा। यह बात उज्जैन से पथरे अखाड़ा परिषद के संतजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का समान करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सभी संतों ने खाली और फूलों की बड़ी माला पकानक अधिनंदन किया एवं आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सनातन परंपरा का पालन करते हुए संतजनों का भोपाल (ए)। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी संतों को उज्जैन में विकास कार्यों की जानकारी दी और उनके सुखाव प्राप्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिष्य नवी के जल संरक्षण, उज्जैन में स्वच्छता, अखाड़ों के निर्माण की योजना, जल निकायी, आगमी कृष्ण की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी संतजनों को निवास पर भौजन कराया तथा स्वयं भी संतों के साथ भौजन किया। मुख्यमंत्री निवास पर अखाड़ा परिषद उज्जैन के अध्यक्ष महंत श्री रामेश्वरदास जी महाराज, महंत श्री रामचन्द्र दास जी महाराज दिग्बार अखाड़ा, महंत श्री रामगणीरी जी महाराज, महंत श्री रामेश्वरद दास जी महाराज, महंत श्री सुमन्दर गिरी जी महाराज, महंत श्री लिंगिवर्ज दास जी महाराज, महंत श्री सुमन्दर गिरी जी महाराज अखाड़ा, महंत श्री सुरेशानंद गिरी जी महाराज, महंत श्री कृष्णानंद जी महाराज, महंत श्री रमेशनंद ब्रह्मचरी जी, महंत श्री मंगलदास जी महाराज नवा अखाड़ा, महंत श्री राजेन्द्र गिरी जी महाराज अखान अखाड़ा, महंत श्री विश्वलालास जी महाराज, महंत श्री राधवेन्द्रदास महाराज और महंत श्री देवगिरी जी महाराज सहित अन्य संतजन उपस्थित रहे।

हरदा में बिजली कंपनी के 15 पोल तोड़ने के आरोप में 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

भोपाल (ए)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी का विकास कार्यक्रम के हरदा वृत्त के मसनगांव वितरण केन्द्र अंतर्गत गैरकान्ती रूप से बिजली लाइन के 15 पोल तोड़ने पर तीन आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मसनगांव वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक प्रदीप बुमराह डॉले के अवेदन पर थाना छिपावड द्वारा तेजराम विश्वास, अनिल विश्वास के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 324 (5), मप्र समर्पित विरुप्पा निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 एवं 140 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। गौरतलब है कि कंपनी मसनगांव केन्द्र के सहायक प्रबंधक प्रदीप बुमराह डॉले ने बताया की मसनगांव केन्द्र के 15 की तरफ ये केन्द्र जामली से निकलने वाली नवीन 11 की बीच धरेलू लाइन का कार्य किया गया था। जिसमें 27 अक्टूबर 2024 को रोत्रि में लगभग 1 बजे साधारण पिता कृष्ण बिश्वास ग्राम बड़नगर के खेत में 8 पोल एवं पवन पिता मुकेश बिश्वास ग्राम बड़नगर के खेत में 7 पोल, इस तरह से कुल 15 पोल तोड़े गए हैं। इसमें तेजराम पिता जगत्राय विश्वास निवासी ग्राम बड़नगर, अनिल पिता श्रीकृष्ण विश्वास निवासी ग्राम बड़नगर तथा अमित पिता अमृतलाल विश्वास ग्राम खमलाय एवं उनके साथियों के खिलाफ पोल तोड़ने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

दीपावली पर्व पर रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वालों को बाजारी कर से पूछ नगरी विकास एवं आवास विभाग ने जारी किये आदेश



प्रदेश के नगरीय निकायों में हरित क्षेत्र के विकास के लिये 390 योजनाओं को स्वीकृति

अमृत 2.0 में स्वीकृत योजनाओं पर खर्च होगे 118 करोड़ रुपये



भोपाल (ए)। प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिये व्यवसाय करने पर अधिकारी ने इस संबंध में नारीय विकास एवं आवास विभाग को उद्देश्य सहीरी इलाकों में हरित स्थानों का विकास एवं कार्यादार पौधरोपण योग्य उपलब्ध कराया है। इन योजनाओं के साथ नारियों के शहरी जीवन की उपगवाता में सुधार आयेगा। साथ ही पार्कों में बच्चों के खेलने के स्थान को नारियों के लिये विश्राम स्थल, वांकिंग ट्रैक, और योग इस संबंध में लगने वाली दुकानों पर सफ-सफाई और आवास की स्थानों के विकास में लिये स्थानीय निकायों की पौध-रोपण के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। इन पार्कों को उद्देश्य से लगाया जायेगा। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवम्बर, 2024 (वारस पर्व) के त्रिप्रावशील रहेगा। यह आदेश एवं आधिकारी ने जारी किया है।

जलवायु परिवर्तन को रोकने जमीनी स्तर पर व्यवहार में लाना होगा बदलाव

जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास - भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर हुई संगोष्ठी

विभिन्न विषयों हुए पैनल डिस्क्यूशन

में वकारों ने रखे विचार

भोपाल (ए)। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये जमीनी स्तर पर व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबासूत की जो बात की गई है, उसका पालन सभी को करना चाहिए। भारत हेमा प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में सामने आया है। विषय-विशेषज्ञों ने इस तरह के विचार जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास - भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों को योगदान पर हुई संगोष्ठी में इंडिया एसपीसीट और कलाइमेट प्रोटोकॉल एवं नेटरेट एड इंटरनेशनल लेवल्स पर हुए पैनल डिस्क्यूशन में लिये आये हैं।

क्लाइमेट जस्टिस जरूरी

सेवानिवृत्त आईएस रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कावन बाजारों में प्रवेश के लिये थोस फैमिलर्स बनाने की जरूरत है। इससे प्राकृतिक खेती और सतत अस्थायी एवं पर्यावरणीय प्रयासों को विस्तृत सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा बल्कि भारत की वैश्विक हरित अस्थायवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थापित करेगा। श्री प्रसाद कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, अतः कलाइमेट जस्टिस जरूरी है।

एक भी बूढ़ा यानी का नहीं छोड़ता

आईआईएफएप के प्रोफेसर डॉ. योगेश दुबे ने कहा कि कलाइमेट चेंज को रोकने के लिये भारत सरकार के विश्वविद्यालयों एवं पर्यावरणीय संसाधनों पर उपर्युक्त कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिये योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जलवायु विश्वविद्यालय का सभी कार्यों का अध्ययन करते हुए पड़ता हूं। इसमें कलाइमेट चेंज को सहायता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय का अध्ययन करना चाहिए।

बनायें नेचर वॉलेटर्स

वरिष्ठ परबरान की अभियान खांडेकर ने कहा कि जमीनी स्तर पर व्यवहार में राज्यों का योगदान विषय पर हुई संगोष्ठी

विभिन्न विषयों हुए पैनल डिस्क्यूशन

में वकारों ने रखे विचार

जलवायु परिवर्तन को रोकने जमीनी स्तर पर व्यवहार में लाना होगा बदलाव

जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास - भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर हुई संगोष्ठी

विभिन्न विषयों हुए पैनल डिस्क्यूशन

में वकारों ने रखे विचार

जलवायु परिवर्तन को रोकने जमीनी स्तर पर व्यवहार में लाना होगा बदलाव

जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास - भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर हुई संगोष्ठी

विभिन्न विषयों हुए पैनल डिस्क्यूशन

में वकारों ने रखे विचार

जलवायु परिवर्तन को रोकने जमीनी स्तर पर व्यवहार में लाना होगा बदलाव

जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास - भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर हुई संगोष्ठी

विभिन्न विषयों हुए पैनल डिस्क्यूशन

में वकारों ने रखे विचार

जलवायु परिवर्तन को रोकने जमीनी स्तर पर व्यवहार में लाना होगा बदलाव

जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास - भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर हुई संगोष्ठी

विभिन्न विषयों हुए पैनल डिस्क्यूशन

में वकारों ने रखे विचार</p

सर्प के काटने से मृत्यु होने पर चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। इन्होंने काटने के बाद जीवन नहीं बचा सका। इन्होंने अन्दर सुखनगर की 29 अगस्त 2024 को सर्प के काटने के कारण मृत्यु हो जाने पर मृतक के बैध वारिसान उसके पुत्र रमेश पिता नव भावोर विवाही ग्राम गुलाली तहसील मध्यनगर की राजस्व पुस्तक परिवर्त 6(4) की कोडिका पाँच बिंदु क्रमांक 2-के प्रावधानों के तहत 4,00,000 (चार लाख रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।

माटी कला शिल्पियों द्वारा दीपावली पर विस्तृत के लिए तैयार उत्पादों पर कर नहीं वसूलने के निर्देश

जबलपुर (उ.) | कलेक्टर दीपक सक्सेना ने माटी कला शिल्पियों द्वारा परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले दीपक, खिलौने, सजावटी समान एवं मिट्टी के अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विकासों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने वाले हाट बाजारों में इन्हें उत्तर स्थान उपलब्ध कराने एवं किसी भी प्रकार की कर वसूलन करने के लिए अधिकारियों को दिए हैं। इस बारे में जारी आदेश में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि माटी कला शिल्पियों द्वारा परंपरागत रूप से बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (वर्ष 2024-25) की द्वितीय किसित अंतरित करेंगे। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों के 1624 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अंतर्ण किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सकारार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को लाभान्वित कर रही है। इन दोनों योजनाओं में इन्हें उत्तर स्थान उपलब्ध कराने एवं किसी भी प्रकार की कर वसूलन करने के लिए अधिकारियों को दिए हैं। इस बारे में जारी आदेश में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि माटी कला शिल्पियों द्वारा परंपरागत रूप से बनाया जायेगा। मिट्टी के दीपक एवं अन्य उत्पाद बाजारे जाते हैं और इन्हें विभिन्न त्वाहों के अवसरों पर बाजारों में विक्रय के लिए लाया जाता है। मिट्टी शिल्पकाला इन कलाकारों के जीवन यापन का मुख्य आधार है।

ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण विजली कर्मचारियों को रियायत दर पर मिलेंगे

इन्होंने (उ.) | ऊर्जा विभाग के लिए शासुरास परिवर्तन लेते विजुल वितरण कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों को भी ऊर्जा दक्षता योजना लिसिसेड (EESL) की योजना के अनुसार 5 स्टॉर्ट श्रेणी के विद्युत उपकरण ऑन लाइन प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश रिंग चौहान ने बताया कि ऊर्जा दक्षता का बढ़ावा देने के लिए शासन के लिए सकारारी कर्मचारी उपकरण योजना लागू की है। इसका लाइसेन्स सहायता योजना के बैच ऊर्जा दक्षता योजना और जागरूकता लाना, ऊर्जा दक्षता वाले विद्युत उपकरण जैसे एलईडी, फ्रीज, पैंसे, एरर कंडीशनर, इंडक्शन कुक्स और ट्रोटर, कम्प्यूटर ग्राउंड पर EESLmart-in पर जाए। इसके बाद उपकरणों के लिए एसएल मिलेगी, शासकीय ईमेल आईडी से लोगों करने पर विद्यायत का उल्लेख मिलेगा। इसके बाद नाम, पता लिखकर ऑर्डर करके रियायती दर पर विक्रय का विकल्प चुना जा सकेगा।

अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रधानमंत्री श्री मोदी 29 अक्टूबर को प्रदेश के किसानों के स्वातों में करेंगे सहायता राशि अंतरित

इन्होंने (ए.) | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिए नये आयाम लायेंगे कि ये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतृत्व में जीवन में भी निरंतर दिखाव दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (वर्ष 2024-25) की द्वितीय किसित अंतरित करेंगे। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों के 1624 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अंतर्ण किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सकारार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को लाभान्वित कर रही है। इन दोनों योजनाओं में इन्हें उत्तर स्थान उपलब्ध कराने एवं किसी भी प्रकार की कर वसूलन करने के लिए अधिकारियों को दिए हैं। इस बारे में जारी आदेश में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि माटी कला शिल्पियों द्वारा परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले दीपक, खिलौने, सजावटी समान एवं मिट्टी के अन्य उत्पादों को बढ़ाव देने के लिए स्थानीय विकासों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने वाले हाट बाजारों में इन्हें उत्तर स्थान उपलब्ध कराने के लिए लायेंगे।



किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रुपये का लाभ प्रदेश किया जा रहा है। अब तक म.प्र. के किसानों के बैंक खातों में 41 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि अंतरित दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वर्ष 2024-25 बजट में 66 हजार 605 करोड़ रुपये

का प्रबंधन करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए स्थन्य प्रतिवर्त ब्याज दर पर कृषकों के अल्पवार्षिक फसल रुपये दिये जाएंगे। किसानों को जीवन में पहली बार रुपये के लिए जीवन को जीवन में पहली बार रुपये का प्रबंधन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए रुपये की राशि अंतरित दी जा चुकी है।

किसानों को जीवन में पहली बार रुपये का प्रबंधन किया गया है। अब तक म.प्र. के किसानों के बैंक खातों में 41 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि अंतरित दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए रुपये की राशि अंतरित दी जा चुकी है।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करने प्रगत रथ रवाना करेंगे।

नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागर

सम्पादकीय



अभियंता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है,
सत्य प्रसुत करना हमारा कर्त्तव्य

फॉर्मूला किस हृद तक न्यूनतम

सार यह कि भारतीय आवादी का बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी का मारा है। जबकि गरीबी मापने का विश्व बैंक का पैमाना खुद आलोचनाओं के केंद्र में रहा है। अनेक विशेषज्ञों ने इसे अति-न्यूनम पैमाना बताया है विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में माना है कि 2020 (यानी कोरोना काल) के बाद से भारत सहित दुनिया में गरीबी घटने की प्रक्रिया ठहर गई है। बैंक का ताजा आकलन है कि भारत में इस समय 12 करोड़ 90 लाख लोग चरम गरीबी की अवस्था में जो रहे हैं। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। इसलिए उसका कहना है कि भारत पर चरम गरीबी का पैमाना 6.85 डॉलर प्रति दिन (पीपीपी में तकरीबन 139 रुपये) लगू होना चाहिए। इस कसौटी पर देखें, तो भारत में 43 करोड़ से अधिक लोग चरम गरीबी की अवस्था में हैं। यह संख्या 1990 में भारत में चरम गरीबी सीमा के नीचे आने वाले कुल लोगों की संख्या से ज्यादा है (तब भारत की जनसंख्या लगभग 88 करोड़ थी)। विश्व बैंक ने भारत सरकार की तरफ से हाल में जारी घेरेलू उपभोग एवं खर्च सर्वे रिपोर्ट- 2022-23 में अपनाएं गई विधि की आलोचना की है। इस सर्वे के आधार पर सरकार ने भारत में गरीबी मिटाने की दिशा में उल्लंघनों प्रगति का दावा किया था। यानी कुल सार यह है कि भारत में गरीबी के मारे लोग आज भी बड़ी संख्या में हैं। जबकि गरीबी मापने का विश्व बैंक का पैमाना खुद आलोचनाओं के केंद्र में रहा है। अनेक विशेषज्ञों ने इसे मनमाने द्वारा से तैयार किया गया न्यूनतम पैमाना बताया है। अगर गौर करें कि मध्यम आय प्रेणी वाले भारत जैसे देश में रोज 139 रुपये खर्च क्षमता वाले व्यक्ति को विश्व बैंक गरीब नहीं मानता, तो समझा जा सकता है कि यह फॉर्मूला किस हृद तक न्यूनतम है। आखिर इतनी रकम के साथ कोई व्यक्ति किस स्तर का उपयोग कर सकता है? बहरहाल, इस फॉर्मूले के मुताबिक भी सबसे तेजी गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था की यह सूख उभरी है, हमरे विकास की दिशा क्या है, यह खुद जाहिर हो जाता है।



अयोध्या में आगामी दिवाली समारोह की तैयारियों के तहत राम की पैड़ी पर मिट्टी के दीये सजाते कार्यक्रम।

धनतेरस से दीपावली का शर्कानंद-भाई दूज तक पंचदिवसीय महापर्व शुरू

- किशन सन्मुखदास भावनानी

वैश्विक स्तर पर अगर हम गहराई से देखें तो भारत में कीरीब कीरीब हर दिन किसी न किसी पर्व के मनाने का होता है। कभी सामाजिक जातीय धार्मिक, राष्ट्रीय तो कभी चुनावी महापर्व जैसे 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी महापर्व तथा 23 नवंबर 2024 को परिणाम आने का महापर्व मनाने का दिन है, इन त्योहारों का एक महत्वपूर्ण अनेकता में एकता है, इसके कारण ही भारत एक विश्वलकाय जनसंख्या वाला देश विभिन्न धर्मों जातियों के बीच सर्वधर्म सद्वाक्र के प्रेम से संयोग हुआ एक ख्वासूरत गुलदस्ता है, इसीलिए ही हर धर्म समाज का पर्व हर दिन आनास्वाधारिक है। परंतु उत्कृष्ट पर्वों में से धनतेरस से दीपावली और फिर छठ महापर्व एक ऐसा ख्वासूरत त्योहार पर्व है जिसे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बसे भारतविश्वायों द्वारा बड़े धूमधार से मनाया जाता है, जिसके शुरूआत 29 अक्टूबर 2024 से हो गई है जो 5 दिन तक बड़ी साहार्दपूर्ण के साथ और ख्वाशियों के साथ मनाया जाएगा, जो धार्मिक आस्था का ख्वासूरत प्रतीक है। चुंकि दीप जले दीपावली आई, धनतेरस से दीपावली का आगाज़ कर दिया है और पांच दिवसीय दीपावली पर का धनतेरस के भावपूर्ण स्वतंत्रता से शुरू हो गया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के साथ योग्य देखने के लिए अधिक धूमधार धनतेरस मनाने हैं। आज के दिन ही बहुत समय बीच आ रहे मनो मालिन्य को त्याग कर यमराज ने अपनी बहिन यमुना से मिलने हेतु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्तुत व उपरांत एवं दीपावली के स्वास्थ्य लाभ हो। साथियों बाट आग लगाए होंगे दीपावली महाराष्ट्र की संख्या वाली घेरेलू उपभोग एवं खर्च सर्वे रिपोर्ट- 2022-23 में अपनाएं गई विधि की आलोचना की है। इस सर्वे के आधार पर सरकार ने भारत में गरीबी मिटाने की दिशा में उल्लंघनों प्रगति का दावा किया था। यानी कोरोना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन बैठती है। वैसे विश्व बैंक ने चुंकि भारत को मध्यम आय वाले देशों की प्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का चरम गरीबी का पैमाना 2.15 डॉलर प्रति दिन (परेरेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी- के अर्थ में) से कम खर्च क्षमत है। पीपीपी पर यह रकम फिलहाल लगभग 44 रुपये प्रतिदिन



मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024, सीहोर

वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, कई हिस्सों में छाया धुंआ

हवा में सांस लेना आम जनता के लिए काफी मुश्किल भरा



नई दिल्ली (ए)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों हवा में सांस लेना आम जनता के लिए काफी मुश्किल भरा हो रहा है। हवा में लगातार प्रदूषण घूल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में धूंध की परत छाई रही और सामग्री को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। सफर ने आप से वाले अतिरिक्त उत्सर्जन के कारण राजधानी में आप से वाले साथ में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। सफर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, प्रदूषकों के प्रभावी फैलाव के लिए मौसम संबंधी परिस्थितियां प्रतिक्रिया हैं। दिल्ली के एक छाया वर्षा अग्रवाल ने सरकार से राजधानी शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकों और नवाचार का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने एनएआई से कहा, वाहन और औद्योगिक प्रदूषण सहित प्रदूषण में वृद्धि के कई कारण हैं। भले ही यह बाहन जा रहा है कि दिल्ली के कारण यह बढ़ रहा है, लेकिन इसके बारे में वृद्धि के कारण राजधानी के क्षेत्र में विनियोग के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यहां बहुत सारे इंजीनियरिंग कालेज हैं, किसी तरह हमें नई तकनीकों और नवाचारों का उपयोग करना चाहिए, सरकार को इसे नियंत्रित करना चाहिए और इसका राजनीतिकरण करने के बजाय कुछ कदम उठाने चाहिए।

29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रात बारह बजे तक श्रद्धालु निहार सकेंगे श्रीराम मंदिर की भव्य सजावट

अयोध्या (ए)। योगी सरकार इस वर्ष अयोध्या में आठवें दीपांत्सव का भव्य आयोजन कर रही है। इस अवसर पर अयोध्या नगरी को दीपों से रोशन करने और श्रीराम जन्मभूमि पर बने नव और भव्य मंदिर में पहली दीपावली को अविसरणीय बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वर्ष समय तट पर जहां 25 से 28 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है, वहां श्रीराम मंदिर में विशेष प्रकार के दीपक जलाएं जाएंगे। मंदिर भवन को दाग-धब्बों और कलाकृति से सुरक्षित रखने के लिए विशेष दीपों की व्यवस्था की है, जो लंबे समय तक प्रकाशन करते हैं।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाने की भी विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर भवन के ढाँचे को धुएं की कालिख से बचाने के लिए परिस्य में विशेष मोम के दीपक जलाएं जाएंगे, जिससे कार्बन न्यूट्रिटम अयोध्या न केवल धूम और आस्था का केंद्र बने, बल्कि स्वच्छा और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दें। दीपोत्सव की भव्यता को अद्वितीयों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर को 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक रात 12 बजे तक बारह से भवन दर्शन के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है।



प्रदूषण से निपटने की तैयारी में दिल्ली सरकार, 10,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर होंगे तैनात

नई दिल्ली (ए)। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाने हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने विभिन्न एजेंसियों में 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को बढ़ावा करने की योग्यांकों को घोषणा की। इन स्वयंसेवकों को प्रदूषण फैलावों में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे दिल्ली की खतरनाक वायु गुणवत्ता के स्तर के खिलाफ चर्छी लड़ाई को खतरनाक वायु गुणवत्ता के लिए एक सक्रिय कार्यवाही की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति में परिवर्तित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और अगर कोई गलती हुई है तो उसे दूर किया जाएगा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिह्नित करने के आरोप

किसानों की जमीन को बता दिया था वक्फ की प्रॉपर्टी, अब कर्नाटक सरकार ने लिया धू-टर्न

बैंगलूरु (ए)। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि उहां जारी नोटिस वापस लिए जाएंगे और उपायुक्त इस गलती की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति में परिवर्तित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और अगर कोई गलती हुई है तो उसे दूर किया जाएगा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिह्नित करने के आरोप

हेरोफेरी का आरोप सामने आया था। इसमें कहा गया था कि केवल 21 दिनों में 44 संपत्तियों का स्थानिय हातान्तरित करने के लिए जारी रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड पर कर्नाटक में 1,00,000 एकड़ जमीन पर दावा करने का आरोप आया था। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि उहां जारी नोटिस वापस लिए जाएंगे और उपायुक्त इस गलती की जांच करेंगे।

इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 12 से 31 अक्टूबर तक उपरी गंगा नदर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्याह्न तक उत्तर प्रदेश के नदर बंद कर दी गई थी। विज्ञिति में आगे कहा कि इस बंद अवधि के दौरान, आइजोल से ध्वनिक विभाग और उत्तर प्रदेश से ध्वनिक विभाग ने गंगा नदी को बढ़ावा दिया है। इसपर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा

